ing capacities are available under Operation Flood (Jan. 1989):—

Processing	—128.9 Ilpd
Chilling	—52.4 Ilpd
Metro Marketing	—36.4 Ilpd
Mill powder production capacity	—624.5 MT/day

(Ilpd—lakh litres per day).

Processing facilities are created to provide essentially to meet the peak season procurement which is generally 50 per cent more than the lean season procurement. The average capacity utilisation of milk plants in January, 1989 in the Operation Flood projects area, was about 86 per cent and in 34 milksheds, the utilisation exceeded the capacity.

Utilisation of Milk Powder Plants

529. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the NDDB purchased 8 large size milk powder plants costing Rs. 22 crore while the capacity utilisation of the existing plants is hardly 20 per cent:

(b) if so, what are the reasons for purchasing large size milk powder plants at an enormous cost when the existing capacity of the plants is not being fuliy utilised; and

(c) the steps Government propose to take for full utilisation of these plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) to (c) National Dairy Development Board has purchased 8 Milk Powder plants, each of 30 M.T. capacity, costing around Rs. 24 crores. As of January, 1989 the capacity utilisation of existing plants under Operation Flood was 60 per cent.

Powder plants are needed for conservation of milk mainly during flush season and to meet the demand of liquid milk during lean season by recombination. The creation of adequate powder plant capacities is also dictated by the needs of future planning for meeting the ever increasing demand for liquid milk. Large size powder plants with advanced technology are considered more cost effective.

मध्य प्रदेश के शहरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग

530. **श्री अजीत जोगी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर और ग्वालियर में उनकी जनसंख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें नागरिक-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) पांच शहरों में मलिन बस्ती निवासियों की राज्य सरकार द्वारा 1981 में पता लगाई गई संख्या इस प्रकार है :

शहर	राज्य सरकार द्वारा 1981 में पता लगाए गए मलिन बस्ती निवासियों की संख्या
1. भोपाल	0.568
2. ग्वालियर	0.374
3. इन्दौर	1.263
4. जबलपुर	0.618
5. रायपुर	0.501

(ग) शहरी मलिन बस्तियों में मूल भूत सुविधायें, शहरी मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना की राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत मुहैया कराई जाती हैं। निधियों की व्यवस्था राज्य योजनाओं में की जाती है और राज्य सरकारें अपनी अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार उचित परियोजनायें बनाती तथा कार्यान्वित करती हैं। इस प्रयोजन के लिए कोई सीधी केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों और जे० जे० कालोनियों से उथले हैंड पम्पों का उखाड़ा जाना

531. **श्री कपिल वर्मा :**
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों और जे० जे० कालोनियों से उथले हैंड पम्पों को उखाड़ने का निर्णय किया गया है और यदि हां, तो इन कालोनियों और बस्तियों के नाम क्या-क्या हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) हैंड पम्पों को उखाड़ने की जिम्मेदारी किस प्राधिकरण को सौंपी जायेगी ;

(ग) उथले हैंड पम्पों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन उथले हैंड पम्पों का पानी दूषित पाया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल-व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार 44 पुनर्वास कालोनियों में उथले हैंड पम्पों को हटाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य जून, 1989 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग ने यमुना-पार क्षेत्रों के झुग्गी समूहों में जो 271 हैंड पम्प लगवाए थे, उन्हें पहले ही बारीकी कर दिये गये तथा उन्हें सितम्बर 1988 के बाद के दौरान हटा दिए गए हैं।

(ख) नगर पालिका अंचलों के ऊपर उपायुक्तों के माध्यम से दिल्ली नगर निगम।

(ग) पुनर्वास कालोनियों में लगभग 17,000।

(घ) जी, हां।

विवरण

44 पुनर्वास कालोनियों की सूची

1. बक्करवाला फेज-I
2. बीरपुरा
3. पाण्डव नगर
4. मकूलपुर फेज-I
5. मकूलपुर फेज-II
6. बक्करवाला फेज-III
7. नारायणा
8. मंगोलपुरी
9. जहांगीरपुर
10. खानपुर
11. ज्वालापुरी फेज-I
12. ज्वालापुरी फेज-II
13. नन्द नगरी, ब्लाक-ए से ई
14. नन्द नगरी, ब्लाक-एफ से एल
15. नई सीमापुरी
16. मोची बाग
17. वजीरपुर
18. पुरानी सीमापुरी
19. सीलमपुर फेज-I
20. सीलमपुर फेज-II
21. त्रिलोकपुरी फेज-I तथा II
22. सीलमपुर फेज-II
23. खिचड़ीपुर
24. कल्याणपुरी
25. हिम्मतपुरी
26. सीलमपुर फेज-IV
27. नंगलोई फेज-I